

दि कर्मिक पोस्ट

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 8, अंक : 34

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 12 अप्रैल 2023 से 18 अप्रैल 2023

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

रीसाइक्लिंग के लिए भेजे जा रहे कचरे में बढ़ रही है रेडियोधर्मी प्रदूषण की मात्रा, संयुक्त राष्ट्र ने किया आगाह

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने आगाह किया है कि रेडियोधर्मी सामग्री या उससे दूषित उपकरण तेजी से स्कैप रीसाइक्लिंग चेन में प्रवेश कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। आईएईए ने हाल ही में परमाणु और अन्य रेडियोधर्मी सामग्री की अवैध तस्करी पर वार्षिक आंकड़ें जारी किए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संयुक्त राष्ट्र का एक स्वायत्त संगठन है।

यह नवीनतम आंकड़े आईएईए के आईटीडीबी डेटाबेस से लिए गए हैं, जो इस तरह की रेडियोधर्मी घटनाओं और तस्करी से जुड़ा डेटाबेस है। इस डेटाबेस में करीब 143 सदस्य राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, परमाणु और अन्य रेडियोधर्मी सामग्री की अवैध तस्करी से जुड़ी घटनाओं की जानकारी साझा करती हैं। यह डेटाबेस आईएईए की परमाणु सुरक्षा योजना का ही एक हिस्सा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आम लोगों के लिए इन विशिष्ट घटनाओं का खुलासा नहीं करता है वो केवल सदस्यों द्वारा साझा की गई वार्षिक जानकारी के केवल रुझानों को साझा करता है। इस बार की रिपोर्ट में 31 दिसंबर, 2022 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि इस डेटाबेस के लिए सदस्य घटनाओं को तीन समूहों में रिपोर्ट करते हैं। आईएईए के मुताबिक समूह डू में ऐसी घटनाओं को शामिल किया जाता है जो,

तस्करी या दुर्भावनापूर्ण उपयोग से जुड़ी हैं, या होने की संभावना है, जबकि दूसरे समूह में अनिर्धारित इरादे की घटनाओं को कवर किया जाता है। वहीं समूह III में ऐसी घटनाओं को रिपोर्ट किया जाता है जो तस्करी या दुर्भावनापूर्ण उपयोग से संबंधित नहीं हैं, न उनके होने की संभावना है। देखा जाए तो इस समूह में मुख्य रूप से, अलग-अलग तरह के मैटेरियल की रिकवरी को शामिल किया जाता है, जैसे उनके अनियंत्रित स्रोतों की खोज, अनधिकृत तरीके से निपटान की गई सामग्री का पता लगाना। साथ ही इसमें रेडिएशन से दूषित सामग्री सहित परमाणु या अन्य रेडियोधर्मी मैटेरियल के अनजाने में अनधिकृत कब्जे के साथ-साथ उसके शिपमेंट का पता लगाना शामिल है। परमाणु एजेंसी द्वारा जारी इस नवीनतम डेटासेट के अनुसार, समूह III में रेडियोधर्मी स्रोतों के अनाधिकृत निपटान से जुड़ी प्रमुख घटनाओं को शामिल किया गया है जो स्कैप मेटल या वेस्ट रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री में पहुंच जाते हैं। इस तरह रेडियोधर्मी सामग्री से दूषित यह स्कैप मेटल अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार भेज दिए जाते हैं जहां विभिन्न सामानों में इन रेडियोधर्मी स्रोतों का पता लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, 2022 में ऐसे 130 मामले सामने आए हैं। आईएईए डेटासेट का कहना है, पिछले एक दशक में इस तरह की घटनाओं की औसत वार्षिक संख्या करीब 131 रही है। ऐसे में 2022 में जो घटनाएं सामने



आई है उनको देखकर लगता है कि इन घटनाओं के सामने आने के दर ऐतिहासिक औसत पर जारी है। इस डेटासेट के साथ जारी नोट में यूएन एजेंसी ने कहा कि, ऐसी घटनाओं का होना रेडियोधर्मी सामग्री के नियंत्रण और सुरक्षित निपटान के लिए बनाए सिस्टम में मौजूद कमियों को दर्शाता है।

जानकारी मिली है कि 2003 से 2005 के बीच सामने आई ऐसी घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई थी। आईएईए ने इसका श्रेय स्कैप मेटल सुविधाओं और राष्ट्रीय सीमाओं पर विकिरण निगरानी प्रणालियों में हुई वृद्धि को दिया है।

अनुमान है कि रेडिएशन-युक्त अपशिष्ट उत्पादों के साथ-साथ इनसे दूषित जहाज आदि वाहनों को खतरे की परवाह किए बिना तेजी से रीसायकल किया जा रहा है। जो इस बात को पुख्ता करता है कि 1993-2022 के बीच इस

समूह में रेडियोधर्मी स्रोतों के तहत आधे से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं।

हालांकि ऐसी केवल 10 फीसदी घटनाओं में समृद्ध यूरेनियम, प्लूटोनियम और प्लूटोनियम-बेरिलियम न्यूट्रॉन स्रोत शामिल हैं। इसके बावजूद, कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम युक्त स्कैप मेटल को स्कैपयार्ड में लाया गया था।

इस बारे में आईएईए का कहा है कि, हाल के वर्षों में, इस तरह की घटनाओं की बढ़ती संख्या में मेटल रीसायकल कड़ियों का पता लगाना और रेडियोधर्मी पदार्थों से दूषित वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करना शामिल है। संगठन का कहना है कि यह दर्शाता है कि अब भी कुछ देश रेडियोधर्मी सामग्रियों के अनुचित निपटान को रोकने और पहचानने के लिए संघर्ष कर रहे

हैं। उनके अनुसार इस तरह के प्रदूषण का सबसे आम स्रोत फीड सामग्री है, जो ज्यादातर मामलों में मेटल या उससे निर्मित उत्पाद होते हैं। स्वास्थ्य के लिए खतरा तब और बढ़ जाता है जब इस रेडिएशन-युक्त स्कैप को उपयोग के लिए अन्य उत्पादों में रीसायकल किया जाता है।

ऐसे में आईएईए का इस बारे में कहना है कि, अक्सर मेटल रीसायकल उद्योग से बहुत अधिक मात्रा में फीड सामग्री प्राप्त की जाती है और उसे पिघलाया जाता है। यह स्कैप अज्ञात रेडियोधर्मी स्रोतों जैसे कोबाल्ट - 60 आदि से दूषित हो सकते हैं। आईएईए ने चेतावनी दी है कि, इन दूषित मेटल को यदि घरेलू सामान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तो वो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है।



छत्तीसगढ़ में वर्षों से जमा कचरे का जल्द से जल्द किया जाए निपटान, एनजीटी ने दिए निर्देश

रायपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करने के साथ-साथ तय समय सीमा के भीतर आवश्यक सीवेज प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने 31 मार्च, 2023 को दिए अपने आदेश में प्रदूषण को रोकने के लिए जरूरी उपाय करने का भी निर्देश दिया है।

मुख्य सचिव के अनुसार इसके लिए कम से कम 1,000 करोड़ रुपये की रिंग-फेंस राशि को अलग रखा जाना है। साथ ही इस राशि को नॉन लैप्सेबल रखा जाना चाहिए। वहीं कोर्ट का निर्देश है कि सात शहरी स्थानीय निकायों में वर्षों से जमा कचरे को बिना किसी देरी के ट्रीट किया जाना चाहिए। अगली रिपोर्ट में इस बात का जिक्र होना चाहिए कि कोई कचरा शेष नहीं बचा है। साथ ही कोर्ट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और प्रस्तावित एसटीपी के बीच तत्काल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने की बात कही है। पीठ ने आशा व्यक्त की है कि छत्तीसगढ़ नए दृष्टिकोण और कड़ी निगरानी के जरिए इस मामले में जरूरी उपाय करेगा। पीठ ने यह भी उम्मीद जताई है कि सरकार वर्षों से जमा कचरे के साथ-साथ बिना प्रोसेस कचरे और तरल अपशिष्ट के उत्पादन और उपचार के बीच जो अंतर की खाई है उसे जल्द से जल्द भर देगा।

हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर में किया जा रहा सीवेज का निपटान, समिति ने की एसटीपी के निर्माण की सिफारिश ग्रेटर हैदराबाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित जल निकायों में दूषित सीवेज का निपटान किया जा रहा है। यह जानकारी 3 जनवरी, 2023 को एनजीटी के आदेश पर गठित संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में दी है। मामले तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद का है। इस मामले में हैदराबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर देवेश निगम ने एनजीटी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में उन्होंने बताया कि तेलंगाना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (टीआईएमएस) के साथ आस-पास की कॉलोनिंग से भी दूषित सीवेज और मेडिकल वेस्ट केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर में डाला जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने एक संयुक्त समिति का गठन किया था। इस समिति को मामले की जांच करने के साथ, इससे जुड़ी जानकारीएं एकत्र करने और की गई कार्रवाई पर दो महीनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस बारे में हैदराबाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने संयुक्त समिति को जानकारी दी है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के परिसर में चार जल निकाय मौजूद हैं। इनमें मोर झील, चिलाकला कुंटा, गुंडला कुंटा और गुनेरू कुंटा शामिल हैं।



कोयले का इस्तेमाल बंद करने की गति बहुत धीमी, तीन डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ रही है दुनिया

मुंबई। दुनिया भर में कोयले से बिजली पैदा करने में जिस रफ्तार से कमी आने की सोची गई थी, वैसा नहीं हो रहा है। पेरिस समझौते का अधिकतम दो डिग्री तापमान का लक्ष्य विफल होता दिख रहा है और दुनिया 2.5 से तीन डिग्री तापमान में वृद्धि की ओर बढ़ रही है। एक नए अध्ययन में यह बात कही गई है कि बढ़ते तापमान से बचा जा सकता है। यह अध्ययन चार्ल्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है।

प्रोफेसर अलेह चेरप ने कहा कि, अधिक से अधिक देश वादा कर रहे हैं कि वे अपनी ऊर्जा प्रणालियों से कोयले को चरणबद्ध तरीके से हटा देंगे, जो आशाजनक लगता है।

लेकिन दुर्भाग्य से, वायदे उतने मजबूत नहीं हैं जितने होने चाहिए। उन्होंने कहा कि, कोयले से तेजी से बाहर निकलने की जरूरत है, चेरप, लुंड विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल एनवायर्नमेंटल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। चीन और अमेरिका जैसे देश जो बिजली पैदा करने में कोयले का सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं, इन जैसे देशों ने अभी तक कोयले को चरणबद्ध तरीके से हटाने का वायदा नहीं किया है। पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में दुनिया के तापमान में वृद्धि को दो डिग्री से नीचे रखने के लिए कोयले को चरणबद्ध रूप से बाहर करना आवश्यक है। शोध कार्यक्रम मिस्त्र विद्युतीकरण के एक अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने 2022 से 2050

तक अपने कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए 72 देशों के संकल्प और वायदों का विश्लेषण किया है। सबसे अच्छी स्थिति में, शोधकर्ता बताते हैं कि यह संभव है कि तापमान में वृद्धि दो डिग्री पर बनी रहे। लेकिन यह मानकर चलना कि, अन्य बातों के अलावा, चीन और भारत दोनों ही पांच साल के भीतर अपने कोयले के उपयोग पर लगाम लगाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा, उनके कोयले को चरणबद्ध तरीके से हटाने में उतनी ही तेजी लाने की जरूरत है जितनी ब्रिटेन में हुई है, जो कि सबसे तेज है और जर्मनी द्वारा किए गए वादे से भी तेज है। इससे असमानताएं पैदा हो सकती हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय नीतियों द्वारा हल किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी।

तापमान के तीन डिग्री तक पहुंचने की आशंका

शोधकर्ताओं ने ऐसे परिदृश्य भी विकसित किए हैं जिन्हें वे सबसे वास्तविक मानते हैं। इन परिदृश्यों से पता चलता है कि पृथ्वी 2.5 से तीन डिग्री के ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ रही है। प्रोफेसर जेसिका ज्वेल कहती हैं, देशों की वायदे मजबूत नहीं हैं, यहां तक कि वे कोयला हटाने के सबसे महत्वाकांक्षी देशों में भी शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से कुछ देशों को कोयला खत्म करने से रोका जा सकता है। ज्वेल, चार्ल्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में फिजिकल रिसोर्स थ्योरी के डिवीजन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अध्ययन से पता चलता है कि कोयले से बिजली पैदा करने को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए 72 देशों की प्रतिबद्धताएं एक-दूसरे के समान हैं। प्रतिबद्धताएं ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुरूप हैं कि अतीत में कितनी जल्दी कोयले से बिजली पैदा करने को चरणबद्ध तरीके से हटाया गया था। यदि हमें बढ़ते तापमान से बचना है तो कोयले को हटाने में अब और तेजी लानी होगी। यह अध्ययन एन्वायरनमेंटल रिसर्च लेटर्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का उद्घाटन, पर्यावरण पर होगा विशेष ध्यान



लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सोमवार को दो दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। जिसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन व श्रम एवं

रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कान्क्लेव में लगाए गए एगजीबिशन का भी अवलोकन किया। साथ ही जलवायु परिवर्तन व प्रदेश के वृक्षों पर आधारित पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया। इस अवसर पर प्रदेश के वन पर्यावरण जंतु

उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण कुमार सक्सेना, राज्यमंत्री वन पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री केपी मलिक मौजूद रहे।

लखनऊ में आयोजित किए गए दो दिवसीय नेशनल

क्लाइमेट कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी ने कई मुद्दों पर चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्लाइमेट चेंज एक गंभीर समस्या है। जलवायु परिवर्तन से कई देश प्रभावित हुए हैं। वहीं अक्टूबर में आए बाढ़ से कई जिले प्रभावित हुए थे। इस कॉन्क्लेव में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की

जाएगी। साथ ही कार्बन उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग पर बात भी बात होगी। स्टेट क्लाइमेट चेंज नॉलेज सेंटर के उद्घाटन के दौरान पर्यावरण क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले लोगों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को पूरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बन रहा है। क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का दो दिवसीय आयोजन पर्यावरण क्षेत्र में मील का पत्थर बनेगा। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुए हैं। यह पूरे देश के लिए अनुकरणीय है।

इंदौर में तैयार किया 'वरुणा' सर्वर के साथ पर्यावरण को भी रखेगा सुरक्षित

इंदौर। वैश्विक स्तर पर डेटा की डिमांड बढ़ती जा रही है और इसे सर्वर के माध्यम से सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। डेटा को जिस सर्वर में रखा जाता है उसे वातानुकूलित महौल में रखने के दौरान कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता है वही पानी का भी उपयोग किया जाता है। इंदौर की रेकबेक डेटा सेंटर द्वारा लिक्विड कूलेंट डेटा सेंटर को तैयार कर 'वरुणा' नाम दिया है। इसमें सर्वर को खास तरह के प्रोपराइटरी डाइ इलेक्ट्रिक फ्लूइड में डुबोकर को 22 से 30 डिग्री पर रखा जाता है।

इस तकनीक में सर्वर को 24 घंटे से एसी के तापमान में रखने से निजात मिलेगी। लिक्विड कूलेंट डेटा सेंटर में सर्वर रखने 50



फीसद ऊर्जा बचत होगी। कंपनी द्वारा इसका प्रोटोटाइप तैयार कर उपयोग किया जा रहा है। कंपनी इसका पेटेंट भी हासिल करने की कवायद में जुटी है और अगले दो से तीन माह में यह बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। कंपनी ने अभी 25 किलो वाट क्षमता का लिक्विड कूलेंट डेटा सेंटर तैयार किया है। इसके

बाद 500 किलोवाट का लिक्विड कूलेंट डेटा सेंटर तैयार किया जाएगा, इसका आकार एक कंटेनर के बराबर होगा। अभी जहां एक कमरे के सर्वर रखे जाते हैं वही ये सर्वर पोर्टेबल होंगे जिसके कहीं भी लाया और ले जाया जा सकेगा। लिक्विड कूलेंट वाले

सर्वर की तकनीक उपयोग फिलहाल यूएस व यूरोप में किया जा रहा है। इंदौर की रेकबेक डेटा सेंटर भारत की पहली कंपनी है जिसने स्वदेशी तकनीक पर लिक्विड कूलेंट डेटा सेंटर तैयार किया है। यूएस व यूरोप में जहां इस तकनीक से 25 किलोवाट का सर्वर बनाने में 70 हजार डालर खर्च करना पड़ते हैं। वहीं इंदौर में तैयार किया

गया कूलेंट सर्वर 20 से 25 हजार डालर में उपलब्ध हो सकेगा। विदेशी कूलेंट सर्वर के मुकाबले 50 फीसद कम कीमत में इसे तैयार किया गया है। किसी भी सर्वर से निकलने वाली उष्मा के नियंत्रण के लिए उसे वातानुकूलित स्थिति में रखने की जरूरत होती है। एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के देशों में जहां मौसम गर्म होता है, वहां के लिए कूलेंट सर्वर काफी कारगर रहेगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग तेजी से बढ़ रही है। सामान्य सर्वर के मुकाबले एआइ सर्वर को तीन से चार गुना ज्यादा एनर्जी लगती है। इस तरह के सर्वर को लिक्विड कूलेंट डेटा सेंटर में रखने से ऊर्जा की 50 फीसद से ज्यादा बचत हो सकेगी। भविष्य में डेटा की डिमांड बढ़ती जा रही है।

ग्रेटर हिमालय में तेजी से पिघल रही है छिपी हुई बर्फ - अध्ययन

शिमला। हिमालय को लेकर एक और नया चौंकाने वाला अध्ययन सामने आया है। इस बार यह अध्ययन रिपोर्ट ग्रेटर हिमालय से संबंधित है। यह रिपोर्ट बताती है कि ग्रेटर हिमालय क्षेत्र में अब तक ग्लेशियरों को हो रहे नुकसान को कम करके आंका गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इस क्षेत्र के ग्लेशियरों में आ रहे परिवर्तन को उपग्रहों से सही से देखा नहीं जा सकता।

नए अध्ययन के शोधकर्ताओं ने कहा है कि इससे पहले ग्रेटर हिमालय में जो पिछला आकलन किया गया था, उसमें झीलों में समाने वाले ग्लेशियरों के कुल द्रव्यमान के नुकसान को 6.5 फीसदी कम करके आंका गया था। जबकि मध्य हिमालय में यह आकलन सबसे अधिक था। यहां ग्लेशियरों से बनी झीलों का विकास सबसे तेजी से हो रहा था। यह निरीक्षण बड़े पैमाने पर पानी के नीचे होने वाले बदलावों का पता लगाने में उपग्रह तस्वीरों की

सीमित सीमाओं की वजह से था, जिसके कारण ग्लेशियरों के नुकसान की पूरी सीमा के बारे में अंतर आया। 2000 से 2020 तक क्षेत्र में प्रोग्लेशियल झीलों की संख्या में 47 फीसदी, क्षेत्रफल में 33 फीसदी और मात्रा में 42 फीसदी की वृद्धि हुई। इस विस्तार के कारण लगभग 2.7



गीगा टन ग्लेशियर के द्रव्यमान का नुकसान हुआ, जो 57 करोड़ हाथियों के बराबर या दुनिया में हाथियों की कुल संख्या का 1,000 गुना से अधिक है। इस नुकसान पर पिछले अध्ययनों द्वारा गौर नहीं किया गया था क्योंकि उपयोग किए गए उपग्रह केवल झील के पानी की सतह को माप सकते हैं, लेकिन पानी के नीचे की बर्फ को पानी से नहीं बदला जा सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ़ तिब्बती

पठार अनुसंधान, सीएस के मुख्य अध्ययनकर्ता झांग गुओकिंग ने कहा, इन निष्कर्षों का क्षेत्रीय जल संसाधनों और नुकसान को और अधिक सटीकता से सामने लाया जा सकता है। अध्ययन में ग्लेशियर के बड़े पैमाने पर नुकसान और वैश्विक स्तर पर झील में समाने वाले ग्लेशियरों के बड़े पैमाने पर नुकसान को समझने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है, जो कि 2000 से 2020 के बीच लगभग 211.5 गीगा टन, या मोटे तौर पर 12

फीसदी तक नुकसान होने का अनुमान है। ग्राज यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी के सह-अध्ययनकर्ता टोबियास बोल्च ने कहा, यह अध्ययन क्षेत्र की परवाह किए बिना, भविष्य के बड़े पैमाने पर बदलावों के अनुमानों और ग्लेशियर के विकास मॉडल में झील में समाने वाले ग्लेशियरों से पानी के नुकसान को शामिल करने के महत्व पर जोर देता है। कार्नेगी

मेहन विश्वविद्यालय के एक सह-अध्ययनकर्ता डेविड रोस ने कहा कि लंबे समय में, झील में समाने वाले ग्लेशियरों से बड़े पैमाने पर नुकसान 21वीं सदी में कुल नुकसान में एक प्रमुख योगदानकर्ता बना रह सकता है। मौजूदा अनुमानों की तुलना में अधिक तेजी से बड़े पैमाने पर ग्लेशियरों का नुकसान होने या ये गायब हो सकते हैं। अध्ययनकर्ता ने कहा कि, ग्लेशियरों के बड़े पैमाने पर नुकसान के लिए अधिक सटीक आंकड़ों की मदद से, शोधकर्ता संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र में भविष्य में जल संसाधन की उपलब्धता का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। यह अध्ययन चाइनीज एकेडमी ऑफ़ साइंसेज (सीएस), ऑस्ट्रिया में ग्राज यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी, यूके के सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय और कार्नेगी मेहन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं सहित एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा किया गया है तथा नेचर जियोसाइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

पर्यावरण संरक्षण में विकासशील देशों की मदद करें विकसित देश

लखनऊ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने लखनऊ में आयोजित क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव को संबोधित किया और कहा कि भारत इस मामले में हमेशा से ही गंभीर रहा है। दुनिया में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन विकसित देश करते हैं।

केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में विकसित देशों की ज्यादा भूमिका है। इसका 85 प्रतिशत हिस्सा उनके द्वारा ही उत्सर्जित है। इसलिए विकसित देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए विकासशील देशों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा निवेश आ रहा है जिससे कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी। भारत सदैव से पर्यावरण को लेकर बहुत संजीदा है। हम लगातार स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रयासरत हैं। आरके सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ में क्लाइमेट चेंज पर आयोजित कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। इसमें विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब कोई भी देश इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर एक भी देश में कार्बन उत्सर्जन ज्यादा है तो इसका प्रभाव अन्य देशों पर पड़ना भी तय है। इस दौरान कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपायों पर विचार किया गया ताकि धरती का तापमान कम किया जा सके।

